कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

पत्रांक 286 /मीरजापुर/ दिनांक, मीरजापुर, जुलाई, 16, 2018.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषयः— बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम— ददरी खुर्द, तहसील— सदर, जिला— मीरजापुर मे प्रस्तावित 1320(2x660) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ— भारत सरकार का पत्रांक—8बी/08/38/2016/एफ.सी./478 दिनांक 11.01.2017, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक— 2691/14—2—2018—800(64)/ 2016 दिनांक 27.08.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 469/11—सी—FC/UP/Thermal/14236/2015 लखनऊ दिनांक 29.08.2018. तथा पत्रांक 2173/11—सी—FC/UP/Thermal/14236/2015 लखनऊ दिनांक 17.05.2019, तथा आपका पत्रांक— 5459/मी0क्षे0—33 दिनांक 11.06.2019, पत्रांक— 5734/मी0क्षे0/33 दिनांक 26.06.2019, पत्रांक— 79/मी0क्षे0/33 दिनांक 04.07.2019, इस कार्यालय का पत्रांक—4817/मीरजापुर/15 दिनांक 13.06.2019, उक्त के क्रम में वेलेस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 का पत्र दिनांक 20.06.2019, एवं जिलाधिकारी मीरजापुर का पत्रांक— 846/एस0टी0—शि0 दिनांक 24.06.2019, ।

महोदय,

बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम— ददरी खुर्द, तहसील— सदर, जिला— मीरजापुर मे प्रस्तावित 1320(2x660) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या—3 की वांछित आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। प्रकरण में भारत सरकार के पत्र में उद्घृत - **In pursuance of order of Hon'ble NGT in appeal no 79 of 2014. Department of Forests, UP may review its stand on the proposal** का संज्ञान लेते हुए मा0 एन0जी0टी0 के आदेश में अंकित तत्थ्यो के क्रम में उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार से जांच करायी गयी उनकी जांच आख्या पत्रांक— 05/एस0डी0ओ0/चुनार दिनांक 16.07.2019 द्वारा बिन्दुवार आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध करायी गयी। उक्त के क्रम में आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है।

उक्त परियोजना का आनलाइन प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विचाराधीन है भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य के पत्रांक— 8बी/08/38/2018/एफ0सी0/478 दिनांक 11.01.2017 के बिन्दु संख्या 3 पर यह उल्लेख किया गया है कि **3- In pursuance of order of Hon'ble NGT in appeal no 79 of 2014. Department of Forests, UP may review its stand on the proposal.** अपील संख्या 79/2014 मे दिनांक 21.12.2016 को मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पूरे निर्णय का संज्ञान लेते हुए दिनांक 01.05.2017 को मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्णय आलोक में पुनः वन विभाग द्वारा क्षेत्र की पर्यावरणीय महत्व के क्रम में स्थिति स्पष्ट करते हुए पुनरीक्षण आख्या प्रेषित किया जाना है, जो निम्नवत् है—

परियोजना हेतु बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित 1320(2x660) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा ग्राम— ददरी खुर्द, तहसील— सदर, जिला— मीरजापुर मे लगभग 875 एकड़ भूमि क्रय की गयी है।

अवगत कराना है कि ग्राम— ददरी खुर्द, तहसील— सदर, जिला— मीरजापुर में उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा—117 (6) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या— 617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 के तहत वन विभाग को पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 पर 800 एकड़ एवं पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 248 पर 843 एकड़ भूमि विज्ञापित की गयी है उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखत है "**Particulars of uncultivated land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs**" (संलग्नक—1)।

धारा–4 उप धारा 1(सी) विज्ञप्ति संख्या– 5564 दिनांक 27 दिसम्बर 1955 द्वारा उक्त ग्राम की मात्र 800 एकड़ भूमि धारा–4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत उ0प्र0 गजट में विज्ञापित एवं प्रकाशित की गयी है। **(संलग्नक–2)**

पुनः आंशिक परिस्कार करते हुए विज्ञप्ति संख्या– 23(2)36(ब)/14–ख–67 दिनांक 24 जुलाई 1967 द्वारा मात्र 423 बीघा 12 बिस्वा (264.88 एकड़) रक्षित वन धारा–4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विज्ञापित एवं प्रकाशित की गयी **(संलग्नक–3)**

विज्ञप्ति संख्या–4646/14–2–20 (41)–77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा 419 बीघा 9 बिस्वा (262. 29 एकड़) अन्तर्गत धारा–20 भारतीय वन अधिनियम 1927 रक्षित वन विज्ञापित किया गया **(संलग्नक–4)**।

उपरोक्त के आलोक में प्रस्तावित परियोजना में ग्राम ददरी खुर्द में उपयोग किये जाने वाली भूमि का सक्षम स्तर से विधिक परीक्षण इस समाधान हेतु आवश्यक है कि परियोजना हेतु क्रय की गयी भूमि धारा 117 की विज्ञप्ति से आच्छादित है अथवा नहीं। उक्त परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्या– वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190जी0/2018 दिनांक 28.06.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर का निम्नलिखित प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा :–

"प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या– वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190जी0/2018 दिनांक 28.06.2019 के प्रस्तर–2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।"

प्रस्तावित परियोजना ग्राम– ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जिला– मीरजापुर के सीमा से जुड़े दक्षिण में दांती आरक्षित वन (क्षेत्रफल–7985.00 एकड़), उत्तर में सुखनई आरक्षित वन तथा पूरब में दाढीराम आरक्षित वन (क्षेत्रफल–9309.52 एकड़) स्थित है। इस प्रकार उक्त परियोजना तीन ओर से सघन आरक्षित वन से घिरी हुई है। सम्पूर्ण आरक्षित वन क्षेत्र चैम्पियन एवं सेठ के वनो के वर्गीकरण के अनुसार 5बी/ई–1(एनागाईसेस पेडुला फारेस्ट), 5बी/ई–2 (बांसविलिया सेराटा फारेस्ट), 5बी/ई–5 (ब्यूटिया मोनोस्पर्मा फारेस्ट), 5बी/ई–9 (ड्राई बेम्बू फारेस्ट) शुष्क पर्णपाती वनो की श्रेणी में आता है जो विंध्यक्षेत्र की विशिष्ट वन सम्पदा है।उक्त सम्पूर्ण क्षेत्रफल जैव विविधता से परिपूर्ण है एवं वन्य जीव भालू, काला हिरन, चीतल, सांभर, लकड़बग्घा, सियार, लोमडी, विभिन्न सर्प, आगरा मानीटर लिजार्ड, जंगली बिल्ली, जंगली सूअर, विभिन्न प्रजातियों के पक्षी आदि का वास स्थल है। परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल उपरोक्तानुसार सघन आरक्षित वन से घिरा हुआ है।

निकटतम रेल हेड सरसो प्रस्तावित परियोजना स्थल से 15.500 किमी की दूरी पर है तथा राज्य मार्ग 1.695 किमी0 की दूरी पर है। प्रस्तावित परियोजना में रेलवे तक अप्रोच, मुख्य सड़क से सम्पर्क मार्ग एवं पाइपलाइन कोरिडोर में प्रयुक्त होने वाली भूमि सघन आरक्षित वन भूमि है।

प्रस्तावित परियोजना में 8.3581 हे0 वन भूमि सघन आरक्षित वन क्षेत्र में मुख्य सड़क से सम्पर्क मार्ग एवं पाइप लाइन कोरिडोर हेतु आवश्यक होगी। जिसका गैर वानिकी उपयोग परियोजना में किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित परियोजना का वन्य जीवों (वन्य वनस्पतियों तथा वन्य जन्तुओं) जैव विविधता एवं वनो की साइट क्वालिटी पर कोयले के ढुलान, पाइप लाइन कोरिडोर और सम्पर्क मार्ग के सघन आरक्षित वन क्षेत्र से गुजरने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

सम्पूर्ण वन क्षेत्र पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील है। सम्पूर्ण क्षेत्रफल में क्वार्टजाइट, सैण्ड स्टोन आदि खनिज की बहुतायत है जो कि विन्ध्यक्षेत्र के विशिष्ट वन क्षेत्रों के विकास में सर्वथा सहायक है एवं शरीसृप वर्ग के वन्य जन्तु तथा माइक्रोफ्लोरा की अभिवृद्धि एवं संरक्षण में सहायक है।

प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र के 25.00 किमी0 वाह्य परिधि के अन्तर्गत ही कैमूर वन्य जीव विहार की सीमा आती है। सम्पूर्ण वन क्षेत्र पारिस्थितकीय रूप से संवेदनशील एवं विन्ध्य क्षेत्र का विशिष्ट वन क्षेत्र है।

प्रस्तावित परियोजना के 10.00 किमी की परिधि के अन्तर्गत ही कई टूरिस्ट स्पाट है, यथा विण्ढमफाल, खडंजा फाल, सिद्धनाथ दरी फाल, चूनादरी फाल आदि।

मीरजापुर जनपद में स्थित शुष्क पर्णपाती वन जो की विन्ध्य क्षेत्र के विशिष्ट वन क्षेत्रों में से एक है, के उत्तरी सीमा से गंगा नदी इन्ही विशिष्ट वन क्षेत्रों के जल ग्रहण क्षेत्रों से गुजरने वाली विभिन्न सहायक नदियों के जल को समेटती हुई प्रवाहित होती है।

प्रस्तावित परियोजना के कारण जल ग्रहण क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से सतह जल भण्डारण एवं प्रवाह तथा सम्पूर्ण वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और नदियों की जल वहन क्षमता तथा जल की गुणवत्ता दोनो प्रभावित होगी।

प्रस्तावित परियोजना के कारण पूर्व में स्थापित विभिन्न कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुये श्वांसजनित बीमारियां, वनों की साइट क्वालिटी में गिरावट, वन्य जीवन व जैव विविधता में ह्रास एवं तापमान में वृद्धि तथा भू–जल रिचार्ज में कमी जैसे दुष्प्रभाव तथा समीपवर्ती ग्रामों के निवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

परियोजना में उत्सर्जित फ्लाई ऐश से सम्पूर्ण पादप एवं वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका से इन्कार नही किया जा सकता। फ्लाई ऐश से श्वांसजनित बीमारियां बढने तथा तापीय परियोजना से क्षेत्र के तापमान में भी अनियमित वृद्धि होना स्वाभाविक है।

पूर्व में स्थापित विभिन्न कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों के द्वारा उत्सर्जित फ्लाई ऐश एवं कार्बन डाई आक्साईड, कार्बन मोनोक्साईड एवं अन्य हानिकारक गैसो के कारण निम्नलिखित दुष्प्रभाव परिलक्षित हुए है–

– क्षेत्र के तापमान में वृद्धि
– वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में ह्रास
– वन की साइट गुणवत्ता में ह्रास
– जल संरक्षण में कमी
– भू–जल रिचार्ज में कमी
– सतह जल भण्डारण की गुणवत्ता व मात्रा में कमी।
– श्वांसजनित बीमारियों में वृद्धि
– पुरातात्विक व पर्यटन के क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव
– सम्पूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र पर दुष्प्रभाव
– वन्य जीव मानव संर्घष की घटनाओं में वृद्धि
– नदियों के जल वहन क्षमता व जल की गुणवत्ता में ह्रास।

ये सभी अर्न्तवलित समस्याएं है जो विभिन्न तापीय विद्युत परियोजनाओं के पूर्व के दुष्प्रभावों के अनुभवों पर आधारित है साथ ही ये अप्रत्यक्ष रूप से अगणित समस्याओं को सृजित करेंगी।

इस प्रकार से प्रस्तावित परियोजना के कारण उक्त क्षेत्र की पूरी पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

अतः उपरोक्त के आलोक में पुनरीक्षण आख्या संस्तुति सहित विचारार्थ एवं तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–अपील संख्या– 79/2014 में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्णय के क्रम में प्रभाग से सम्बन्धित बिन्दुवार पुनरीक्षित टिप्पणी।

भवदीय,

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर।

Sl. No.	Judgment Details Para wise	Review regarding stand of Department of Forests. Uttar Pradesh
4	Initially, the appellants submit, a proposal for setting up of the project in question was proposed to be located near villages- Hazipur- Katya, Pahai Goura and Katya, Tehsil Jakhnia and Saidpur, District Ghazipur, UP with land requirement of 850 acres for power plant, green belt and ash pond as per Form-1 dated 31st December, 2010 annexure A-2. However, when the proposal came up for consideration for grant of TOR before the 22nd meeting of the reconstituted Expert Appraisal Committee of Thermal Power and Coal Mine projects held on 4th -5th April, 2011, the information regarding the changed location-District Mirzapur situate at 140Km from the previous location- was submitted as follows:- *"The proposal is for setting up of 2x660 MW Super Critical Coal based Thermal Power Plant at villages Dadri Khurd, in Mirzapur Sadar Taluk, in MirzapurDistt. in Uttar Pradesh.....* *Coal requirements will be 6.4 MTPA. Coal will be obtained from domestic coal block through SECL/NCL/CCL mines.....* *There are no National Parks, Wildlife Sanctuaries, Tiger/Biosphere Reserves etc. within 10 Km of the site. Danti RF, Mirzapur RF, Patehra RF and Gorthara RF is situated within 10 Km from the project site."*	प्रस्तावित परियोजना ग्राम– ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जिला– मीरजापुर के सीमा से जुड़े दक्षिण में दांती आरक्षित वन (क्षेत्रफल–7985.00 एकड़), उत्तर में सुखनई आरक्षित वन तथा पूरब में दाढीराम आरक्षित वन (क्षेत्रफल–9309.52 एकड़) स्थित है। उक्त परियोजना तीन ओर से सघन आरक्षित वन से घिरी हुई है उक्त सम्पूर्ण क्षेत्रफल जैव विविधता से परिपूर्ण है जो वन्य जीव भालू, काला हिरन, सांभर, लकड़बग्गा, सियार, लोमडी, स्याही विभिन्न सर्प, आगरा मानीटर लिजार्ड, जंगली बिल्ली, जंगली सूअर, विभिन्न प्रजातियों के पक्षी आदि का वास स्थल है। परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल उपरोक्त सघन आरक्षित वन से घिरा हुआ है।
6	In the 24th meeting of re-constituted EAC (Thermal) held on 2nd May, 2011 the project proponent along with his consultant M/s J.M Environet Pvt. Ltd. gave a presentation and provided the following information as per the minutes of the meeting- "The proposal is for setting up 2x660 MW Super Critical Coal based Thermal Power Project at villages Dadri Khurd, Mirzapur Sadar Taluk in UP. Land requirement will be 1100 acres, out of which 798 acres is un-irrigated barren land and 77 acres is	प्रस्तावित परियोजना में रेलवे तक अप्रोच, मुख्य सड़क से सम्पर्क मार्ग एवं पाइपलाइन कोरिडोर में प्रयुक्त होने वाली भूमि सघन आरक्षित वन भूमि है। परियोजना हेतु क्रय की गई भूमि का जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा–117(6) के अर्न्गत विज्ञप्ति सं0 617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 का परीक्षण आवश्यक है।

	waste land. 875 acres land will be used for plant and 225 acres land will be used for railway and pipeline corridor..... The project proponent submitted that the Ganges River is about 22Kms from the proposed site and site is not in flood plain of the Ganges. The project proponent also submitted survey of India toposheet in confirmation of their submission. It was also informed that M/s Welspun Energy (U.P) Pvt. Ltd. had conducted pre-feasibility for availability and route of water pipeline from Upper Khajuri Dam till the proposed project site.....The project proponent informed that they have started collection of AAQ data since April and completed monitoring before onset of monsoon. The Committee decided the same can be used for preparation of EIA Report."	
10	The appellants submit that the EAC recommended project for EC overlooking its own observations, siting guidelines and without considering the representations/responses of the affected people, namely Banaras Hindu University and site visit report dated 15th September, 2013. The appellants referred to the following siting criteria laid down by the respondent no.1- MoEF&CC: A. Availability of adequate uncultivable and unused land for erecting power plant structures; B. Vicinity to the railway line for laying railway siding for coal transportation; C. Suitability of land from topography, geological aspects; D. Environmentally suitable, absence of sensitive areas and major settlements.	निकटतम रेल हेड सरसो प्रस्तावित परियोजना स्थल से 15.500 किमी की दूरी पर है तथा राज्य मार्ग 1.695 किमी0 की दूरी पर है। प्रस्तावित परियोजना स्थल को उपरोक्त दोनो से जोड़ने हेतु सघन आरक्षित वन क्षेत्र का उपयोग किया जाना होगा, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता एवं साइट क्वालिटी प्रभावित होगी। सम्पूर्ण आरक्षित वन क्षेत्र चैम्पियन एवं सेठ के वनो के वर्गीकरण के अनुसार 5बी/ई–1(एनागाईसेस पेडुला फारेस्ट), 5बी/ई–2 (बांसविलिया सेराटा फारेस्ट), 5बी/ई–5 (ब्यूटिया मोनोस्पर्मा फारेस्ट), 5बी/ई–9 (ड्राई बेम्बू फारेस्ट) शुष्क पर्णपाती वनो की श्रेणी में आता है जो विंध्यक्षेत्र की विशिष्ट वन सम्पदा है। उक्त सम्पूर्ण वन क्षेत्र पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील है। सम्पूर्ण क्षेत्रफल में क्वार्टजाइट, सैण्ड स्टोन आदि खनिज की बहुतायत है।
14	Despite service of notice to respondent no.2- State of Uttar Pradesh and respondent no.3-Uttar Pradesh Pollution Control Board choose not to file their replies. According to them they had very limited role in the entire process and therefore, no replies are necessary.	उक्त परियोजना का आनलाइन प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विचाराधीन है भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

		क्षेत्रीय कार्यालय मध्य के पत्रांक– 8बी/08/38/2018/एफ0सी0/478 दिनांक 11.01.2017 के बिन्दु संख्या 3 पर यह उल्लेख किया गया है कि **3- In pursuance of order of Hon'ble NGT in appeal no 79 of 2014. Department of Forests, UP may review its stand on the proposal.** अपील संख्या 79/2014 मे मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पूरे निर्णय का संज्ञान लेते हुए दिनांक 01.05.2017 को मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आलोक में विभाग के स्तर से क्षेत्र की पर्यावरणीय महत्व के क्रम में स्थिति स्पष्ट करते हुए पुनरीक्षण आख्या प्रेषित किया जाना है।
29	Material portion of the minutes of EAC meeting dated May 4th and 5th, 2011 at annexure A-4 (page80) reads as under: ***"2.10 2x660 MW Super Critical Coals Based Thermal Power Plant of M/s Welspun Energy UP Private Ltd. at villages Dadri Khurd, in Mirzapur Sadar Taluk, in Mirzapur Distt. in Uttar Pradesh- reg. TOR.*** *"The proposal was earlier placed for consideration in the 22nd meeting held during April 4-5, 2011 wherein the Committee noted that the proposed site may be in the flood plain of river or very close to it and has forests in the vicinity. The Committee also noted that the other sites identified were rejected by the project proponent itself. The Committee therefore decided that the project proponent shall identify more alternative acceptable sites and accordingly deferred the proposal for re-consideration at a later stage.* *The proposal was again placed for re-consideration for determination of terms of reference for undertaking EIA/EMP study as per the provisions of EIA Notification, 2006. The project proponent along with*	प्रस्तर संख्या– 4 के अनुसार। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि ग्राम– ददरी खुर्द, तहसील– सदर, जिला– मीरजापुर में उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–117 (6) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या– 617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 के तहत वन विभाग को पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 पर 800 एकड़ एवं पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 248 पर 843 एकड़ भूमि विज्ञापित की गयी है उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखत है **"Particulars of uncultivated land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs" (संलग्नक–1)।** धारा–4 उप धारा 1(सी) विज्ञप्ति संख्या– 5564 दिनांक 27 दिसम्बर 1955 द्वारा उक्त ग्राम के 800 एकड़ भूमि धारा–4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत उ0प्र0 गजट में विज्ञापित

	its consultant M/s J.M Environet Pvt. Ltd. gave a presentation and provided the following information: *The proposal is for setting up of 2x660 MW Super Critical Coal Based Thermal Power Plant at Villages Dadri Khurd, in Mirzapur Sadar Taluk, in Mirzapur Distt. in Uttar Pradesh. Land requirement will be 1100 acres, out of which 798 acres is unirrigated barren land and 77 acres is waste land. 875 acres land will be used for plant and 225 acres land will be used for railway and pipeline corridor. The co-ordinates of the plant site are at Latitude 24°58'51.2''N to 25°00'5.43''N and Longitude 82°39'34.1''E* *to 82°40'52.71''E. Coal requirements will be 6.4 MTPA. Coal will be obtained from domestic coal block through SECL/NCL/CCL mines. Area requirement for ash/pond dyke will be 225 acres including green belt. Water requirement will be 45 MCM/annum, which will be sourced from the Upper Khajuri Dam and Ganga River through a pipeline about a distance of 4km and 17 km respectively from project site. There are no National parks, Wildlife sanctuaries, Tiger/Biosphere reserves etc. within 10 km of the site. Danti RF, Mirzapur RF, Patehra RF and Gorthara RF are situated within 10 km from the project site.* *The project proponent submitted that Ganges River is about 22 Kms from the proposed site and site is not in the flood plain of the Ganges. The project proponent also submitted Survey of India toposheet in confirmation to their submission. It was also informed that M/s WAPCOS has conducted pre-feasibility for availability and route of water pipeline from Upper Khajuri Dam till the proposed project site.* *The Committee noted that details of water availability need to be extensively examined and a detailed source of water sustainability study shall be submitted.* *The project proponent informed that they have started collection of*	एवं प्रकाशित की गयी है। **(संलग्नक–2)** पुनः आंशिक परिस्कार करते हुए विज्ञप्ति संख्या– 23(2)36(बी)/14–ख–67 दिनांक 24 जुलाई 1967 द्वारा 423 बीघा 12 बिस्वा (264.88 एकड़) रक्षित वन धारा–4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विज्ञापित एवं प्रकाशित की गयी **(संलग्नक–3)** विज्ञप्ति संख्या–4646/14–2–20 (41)–77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा 419 बीघा 9 बिस्वा (262.29 एकड़) अन्तर्गत धारा–20 भारतीय वन अधिनियम 1927 रक्षित वन विज्ञापित किया गया **(संलग्नक–4)**।

	AAQ data since April and complete monitoring before onset of monsoon. The Committee decided that the same can be used for preparation of EIA report. *Based on the information provided and presentation made, the Committee prescribed the following specific ToRs for undertaking detailed study and preparation of EMP.....”*	
34	If one looks at para 7(i) stage II of the EC Regulations, 2006 dealing with the process of scoping it is not difficult to find that all the information furnished in the prescribed application Form-I, forms the basis of detailed and comprehensive Terms of Reference addressing all relevant environmental concerns for the preparation of Environmental Impact Assessment Report in respect of the project for which prior EC is sought in as much as potential impacts of the project are assessed with reference to the information revealed in Form-I. Though, there is no bar on the EAC to consider basic information as a source of information, the EAC has to consider details of the activity in relation to: (i) Construction, operation or decommissioning of the project, involving actions, which will cause physical changes in the locality (topography, land use, changes in water bodies). (ii) Use of natural resources for construction or operation of the project (such as land, water, materials or energy, especially any resources which are non-renewable or in short supply) (iii) Use, storage, transportation, handling or production of substances or materials, which could be harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to human health. (iv) Production of solid wastes during construction or operation or de-commissioning. (v) Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air.	सम्पूर्ण आरक्षित वन क्षेत्र चैम्पियन एवं सेठ के वनो के वर्गीकरण के अनुसार 5बी/ई–1(एनागाईसेस पेडुला फारेस्ट), 5बी/ई–2 (बांसविलिया सेराटा फारेस्ट), 5बी/ई–5 (ब्यूटिया मोनोस्पर्मा फारेस्ट), 5बी/ई–9 (ड्राई बेम्बू फारेस्ट) शुष्क पर्णपाती वनो की श्रेणी में आता है जो विंध्यक्षेत्र की विशिष्ट वन सम्पदा है। उक्त सम्पूर्ण वन क्षेत्र पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील है। सम्पूर्ण क्षेत्रफल में क्वार्टजाइट, सैण्ड स्टोन आदि खनिज की बहुतायत है। परियोजना में उत्सर्जित फ्लाई ऐश से सम्पूर्ण वनस्पति एवं वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। फ्लाई ऐश से सांस जनित बीमारियां बढने तथा तापीय परियोजना से क्षेत्र के तापमान में भी अनियमित वृद्धि होने की सम्भावना है।

(vi) Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat.

(vii) Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground or into sewers, surface waters, ground water, coastal waters or the sea.

(viii) Risk of accidents during construction or operation of the project, which could affect human health or the environment.

(ix) Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead to environmental effects or the potential for cumulative impacts with other existing or planned activities in the locality.

(x) Environmental sensitivity.

Furnished in Form-I

Before detailed and comprehensive Terms of Reference addressing all relevant Environmental concerns for the preparation of Environmental Impact Assessment Report are determined, it is worthwhile to note, the EAC is expected to be pro-active in as much as to look for other information as to would be available, and secondly it has discretion to reject the application at the stage of scoping upon the total view of the material before it and in that context observations made by the Southern Zone Bench of this Tribunal in R. Veeramani's Case regarding the role of the EAC and its authority to vet the information furnished and be bound by it are misplaced as regards the present case. However, in view of the discrepancies pointed out in basic information, Form-I and fresh Form- I furnished by the respondent no.4 as pointed earlier, legitimate questions as regards the objective consideration of the information furnished to the EAC for determining the detailed and comprehensive ToRs arise,. In our view all the information furnished and considered by the EAC for the determination of ToR is a raw material for the Terms of Reference determined from which the draft EIA report takes shape- a material step for further stages of public consultations, appraisal, recommendations of EAC and

	ultimately for grant of EC.	
37	Learned Counsel appearing on behalf of the appellants further invited our attention to IL&FS Technical EIA Guidelines Manual for thermal power plant- August, 2010 prepared for the MoEF, Government of India. Purpose of developing such sector specific technical guideline manual is to provide clear information on EIA to all the stakeholders. It gives guidelines for site selection of coal based thermal power station and general siting factors (page 2748 to 2749). At the outset it exhorts the stakeholders to recognise that no forest land shall be used for non-forest activity and no prime agricultural land shall be converted into industrial site. As regards the site selection for thermal power station, it makes reference to the Guidelines of Central Electricity Authority, Government of India for site selection of coal based thermal power station which advice the selection of site near to coal source, accessibility by road and rail. These guidelines spells out the priorities for site selection as follows: *First priority is given to the sites those are free from forest, habitation and irrigated/agricultural land. Second priority is given to those sites that are barren, i.e. wasteland, intermixed with any other land type, which amounts to 20% of the total land identified for the purpose.*	प्रस्तर संख्या– 10 के अनुसार।
38	Guidelines for site selection of coal thermal power station set by MoEF are made available in the said manual as under: ▪ *Locations of thermal power stations are avoided within 25km of the outer periphery of the following:* *-metropolitan cities;* *-National park and wildlife sanctuaries;* *-Ecologically sensitive areas like tropical forest, biosphere reserve, important lake and coastal areas rich in coral formation;* ▪ *The sites should be chosen in such a way that chimneys*	प्रस्तावित परियोजना तीन ओर से सघन आरक्षित वन क्षेत्र से घिरी हुई है प्रस्तावित परियोजना के 10.00 किमी की परिधि के अन्तर्गत ही कई टूरिस्ट स्पाट है, यथा विण्ढमफाल, खडंजा फाल, सिद्धनाथ दरी फाल , चूना दरी फाल आदि। निकटतम रेल हेड सरसो प्रस्तावित परियोजना स्थल से 15.500 किमी की दूरी पर है तथा राज्य मार्ग 1.695 किमी0 की दूरी पर है। प्रस्तावित परियोजना स्थल को उपरोक्त दोनो से जोड़ने हेतु सघन आरक्षित वन क्षेत्र का उपयोग किया जाना होगा, जिससे क्षेत्र

	of the power plants do not fall within the approach funnel of the runway of the nearest airport; ▪ *Those sites should be chosen which are at least 500m away from the flood plain of river system;* ▪ *Location of the sites are avoided in the vicinity (say 10km) of places of archaeological, historical, cultural/religious/tourist importance and defense installations;* *Forest or prime agriculture lands are avoided for setting up of thermal power houses or ash disposal.*	की जैव विविधता एवं साइट क्वालिटी प्रभावित होगी। सम्पूर्ण आरक्षित वन क्षेत्र चैम्पियन एवं सेठ के वनो के वर्गीकरण के अनुसार 5बी/ई–1(एनागाईसेस पेडुला फारेस्ट), 5बी/ई–2 (बांसविलिया सेराटा फारेस्ट), 5बी/ई–5 (ब्यूटिया मोनोस्पर्मा फारेस्ट), 5बी/ई–9 (ड्राई बेम्बू फारेस्ट) शुष्क पर्णपाती वनो की श्रेणी में आता है जो विंध्यक्षेत्र की विशिष्ट वन सम्पदा है। उक्त सम्पूर्ण वन क्षेत्र पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील है। सम्पूर्ण क्षेत्रफल में क्वार्टजाइट, सैण्ड स्टोन आदि खनिज की बहुतायत है।
39	In this backdrop the contentions raised by the appellants that there was deliberate concealment of forest land by the appellants in the present case gains significance. Learned Counsel appearing on behalf of the appellants submitted that the project proponent concealed the presence of forest within the plant boundary in Form-I dated 3rd December, 2011 as well as in the EIA Report (Page 621) with the statement that there is no forest land within plant boundary.	प्रस्तर संख्या–38 के अनुसार।
40	Perusal of the Form -1 dated 03-12-2011 (page no. 93) reveals clear statement of the fact at entry in serial no. 21-23 of the Form-1 that no forest land is involved and as such, the proposal does not call for clearances under the Forest Conservation Act, 1980. Perusal of the EIA Report (page no. 621) also reveals a categorical assertion that no forest land is within the plant boundary. It is pointed out by the Appellants from the Form-1 that the project envisages approach road connecting SH-5, 15.5 kms distance railway line from Sarsogram railway station and 17 kms of pipeline (31kms as per the EIA Report page no. 601) to fetch water from River Ganga and all this passes through the Reserve Forest.	प्रस्तर संख्या–38 के अनुसार।
44	It is noticed that the WAPCOS team upon visit to the project site (30-09-2011) at Dadri Khurd Village found dense vegetation/forest at Southern-Eastern part	प्रस्तर संख्या–38 के अनुसार।

	of the plant area (page 165). It is also correct that Land Use/Land Cover (LULC) map of District Mirzapur (page no. 2990-2992) shows project area mostly occupied by deciduous forest and part of it by agriculture, plantation. On the other hand, the Project Proponent relies upon the judgments delivered in Application No. 19(THC)/2013 dated 08-08-2014 titled as Nisraga Vs. Assistant Conservator of Forests as well as in New Okhla Bird Sanctuary case [(2011) 1 SCC 744: in In Re construction of park at Noida near Okhla Bird Sanctuary]. The Hon'ble Apex Court in In Re-construction of park at Noida near Okhla Bird Sanctuary case observed as follows: *"In support of the applicant's case that there used to be a forest at the project site he relies upon the report of the CCF based on site inspection and the Google Image and most heavily on the FSI Report based on satellite imagery and analyzed by GSI application. A satellite image may not always reveal the complete story. Let us for a moment come down from the satellite to the earth and see what picture emerges from the government records and how things appear on the ground. In the revenue records, none of the khasras (plots) falling in the project areas was ever show as jungle or forest.."* Moreover, the Appellants admit in their affidavit dated 05-04- 2016 (page no. 2974) that satellite image per se cannot be relied upon as 100% accurate evidence for forest area. However, it proceeds further to state that the time when the said judgments were passed Google Earth Imagery was most common and Bhuvan Application Services were not developed; and Bhuvan Satellite imagery is based on advance technologies like Multi- temporal(satellite images collected repeatedly over a long time for a year or more), multi-layered(superimposing images from different satellites and sensors) and multi-spectral (involving different radiations other than IR radiation), which when collaborated with ground data gives fairly accurate information about the present land use and land cover. Even accepting this statement to be correct its collaboration with the ground data is indispensable for giving fairly accurate	

	information. Ground data collection is, therefore, a key to answer the question whether the land was a forest or forest like area.	
45	We have therefore to see what site inspection reports have procured for the benefit of decision making. Site visit report dated 01-08-2008 makes a reference to the piece of land in Village Kushiyara and Sangra as having been identified in Thesil Lalganj, Haliya, District Mirzapur and having being identified as a forest like area having specified number of trees mentioned therein. It does not say anything about Village Dadri Khurd. Site Inspection Report dated 19-11-2012 (page no. 508) reveals that the inspection of the project site was purportedly carried out by team of Forest Officials, Scientist from MoEF, Project Proponent, Villagers from Mirzapur and Sh. Balram Singh, President, Van Upvan Conservation of Nature Environment Society. The team after going through the reports of the DFO Mirzapur dated 16-08-2013 and 13-09-2013 as well as revenue records of Village Dadri Khurd drew conclusions as follows: 1. *Thus from the records available the proposed Welspum* *Thermal Power Plant site plan included no notified reserved forest/protected forest and forest like area recognized in Mirzapur district in compliance of Hon'ble Supreme Court order.* *The two Gatas 180 and 216 jha with an area of 1.5 ha included in proposed site plan of Welspum Thermal Power Plant is revenue recorded Jhari (forest). The ownership belongs to UP Govt. and it is in process of transfer to the company. If this is used for non-forestry purpose, it requires approval of Central Govt. under Forest (Conservation) Act.*	प्रस्तर संख्या– 4 के अनुसार। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि ग्राम– ददरी खुर्द, तहसील– सदर, जिला– मीरजापुर में उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–117 (6) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या– 617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 के तहत वन विभाग को पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 पर 800 एकड़ एवं पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 248 पर 843 एकड़ भूमि विज्ञापित की गयी है उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखत है **"Particulars of uncultivated land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs"** **(संलग्नक–1)**। धारा–4 उप धारा 1(सी) विज्ञप्ति संख्या– 5564 दिनांक 27 दिसम्बर 1955 द्वारा उक्त ग्राम के 800 एकड़ भूमि धारा–4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत उ0प्र0 गजट में विज्ञापित एवं प्रकाशित की गयी है। **(संलग्नक–2)** पुनः आंशिक परिस्कार करते हुए विज्ञप्ति संख्या– 23(2)36(ब)/14–ख–67 दिनांक 24 जुलाई 1967 द्वारा 423 बीघा 12 बिस्वा (264.88 एकड़) रक्षित वन धारा–4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विज्ञापित एवं प्रकाशित की गयी **(संलग्नक–3)** विज्ञप्ति संख्या–4646/14–2–20 (41)–77 दिनांकित

		20.07.1977 द्वारा 419 बीघा 9 बिस्वा (262.29 एकड़) अन्तर्गत धारा–20 भारतीय वन अधिनियम 1927 रक्षित वन विज्ञापित किया गया (संलग्नक–4 इसके अतिरिक्त प्रस्तावित परियोजना में 8.3581 हे0 वन भूमि सघन आरक्षित वन क्षेत्र में मुख्य सड़क से सम्पर्क मार्ग एवं पाइप लाइन कोरिडोर हेतु आवश्यक होगी। जिसका गैर वानिकी उपयोग परियोजना में किया जाना प्रस्तावित है।
50	Learned Counsel appearing on behalf of the appellants further brought to our notice that not only the project involves use of forest land for coal transportation, water pipeline but there is no discussion in the EIA report regarding the potential impact of the fragmentation of the forest and disturbance of wildlife due to the passing of the railway line for coal transportation, construction of transmission line, water pipeline and approach road. From the facts noticed herein above, it is evident that the project is surrounded by forest and involves 'Parti Bhumi' (fallow land) thereby signifying least anthropogenic activity at or around the project site and, thus the issue of wildlife in the area deserves serious consideration. EIA report (page 668) and the table provided therein (Page 669, 675) make mention of having not noticed any endangered species within the area of project site and the area lying in 10 km of the radius therefrom. However, the appellants pointed out to the response received by them to the RTI query dated 27th August, 2013 (page 161, 162) providing the list of Schedule I species- Sloth Bear, Chinkara, Black Buck, Bengal Monitor, Peafowl, crocodile (Magar) etc. within the project site and 10 km radius area. The project proponent relied upon the bio-diversity assessment and conservation plan and submitted that the EAC in its meeting dated 23rd March, 2014 had found the site report/plan in order. It has been pointed out that the site plan was prepared after the EIA report and public hearing and no study was undertaken to assess the impact of the project and its ancillary activity like coal transportation, water pipeline, approach road, ash ponds and such other impacts on the wildlife in the region. Para	प्रस्तावित परियोजना का वन्य जीवों (वन्य वनस्पतियों तथा वन्य जन्तुओं) एवं जैव विविधता पर कोयले के ढुलान, पाइप लाइन कोरिडोर और सम्पर्क मार्ग के सघन आरक्षित वन क्षेत्र से गुजरने के तथा परियोजना से उत्पादित फ्लाई ऐश से प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

	4.3.1.3 (page 1058) of the report adds credence to this contention in following terms: *"this survey needs to be carried out with the wildlife experts and the State Authority, Department to identify the areas or forest need all the conservation and management interventions which are highly crucial."* Facts revealed before us do not show that any member of the EAC or Expert member of WII conducted any site visit of the project to asses the gravity of exception taken to the project upon the issues raised in relation to the forest and wildlife. Appraisal of the project in this regard, therefore, becomes questionable.	
52	We find from the record, a letter dated 18th September, 2013 (page 174) addressed by Registrar of the Banaras Hindu University to the Secretary, Government of India, MoEF, New Delhi voicing concerns of the University in following words: *I would like to inform you that a Thermal Power Project with capacity 1320 MW Coal based is going to be installed at nearby Village-Dadari Khurd in District-Mirzapur which is 10 km. away from Rajiv Gandhi South Campus of BHU at Barkachha. It is pointed out that the Rajiv Gandhi South Campus is constituent of BHU having running more than 20 self-financing undergraduate and post-graduate courses and other academic activities. A good number of students, teaching and non-teaching staff and their family members are residing in the campus.* *In this connection, we have received a letter of General Secretary, a NGO-"Vindhya Environmental Society" and representation of resident of that area. Further, we have also examined by our Faculty Member who belongs to field of Environmental Science & Technology and he has submitted an Environment Impact Assessment Report of 1320 MW bout proposed Coal based Thermal Power Project, which are self explanatory(copy enclosed).* *It is needless to mention here that the negative impact of this project may adversely affect their health of students, teachers and other staff*	कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है, परन्तु प्रस्तावित परियोजना के कारण विभिन्न कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुये श्वांसजनित बीमारियां, वनों की साइट क्वालिटी में गिरावट, वन्य जीवन व जैव विविधता में ह्रास एवं तापमान में वृद्धि तथा भू–जल रिचार्ज में कमी जैसे दुष्प्रभाव समीप में स्थित बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय, साउथ कैम्पस मीरजापुर, तथा समीप के ग्रामों के निवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

residing in the Rajiv Gandhi South Campus. We would like to highlight the fact that entire drinking water supply of the RGSC is from lower Khajur Dam which is fed by upper Khajuri Dam. Any industrial activity in the upper khajuri Dam will jeopardize our water supply.

Keeping in view of the above fact, I request you to kindly consider for reviewing the shifting of place much ahead from the premises of Rajiv Gandhi South Campus, Barkachha so that the ambiance and environment of this area may keep intact.

This communication from the Registrar enclosed Environment Impact Assessment Report concerning the project in question prepared by Dr. A.K. Pandey, Assistant Professor, Environment Science and Technology, Rajiv Gandhi South Campus, BHU. The respondent no. 4, it appears, made a presentation before the EAC that the issues raised by BHU were resolved in the meeting held on 8th March, 2014 and 10th March, 2014. In that regard our attention has been invited to minutes of the meeting conducted by the project proponent, BHU Faculty and Campus Members on 8th and 10th March, 2014. Reading of these minutes would persuade a reader to believe that discussion was held on following major points:

1. Air Impact and dispersion modelling
2. Water withdrawal scheme
3. Water utilization
4. Waste water management system
5. Coal Quality
6. Coal Transportation.

and after three hours of deliberations it was decided that Welspun Energy UP Pvt. Ltd-Project proponent would be forwarding the

(13)

following commitments to BHU:

1. Installing of ESP with 99.9% efficiency and operating the ESP
2. Commitment to comply all condition stipulated by CWC on water withdrawal
3. Comply with the commitment of ash utilisation plan
4. Commitment to operate ETP

It is further revealed that BHU desired to be part of environmental and social management review during the operational phase of the project and the project proponent should submit six monthly compliance report along with online data as per EC condition to the University along with other stakeholders. Significantly, the minutes of meeting do not disclose what exactly the discussions were in the meeting for thrashing out technical issues involved in the major topics purportedly discussed. The EAC also did a lip service to the process of appraisal by merely recording its nod to the presentation made by the project proponent in following terms:

> 6.The pp has submitted point wise response to BHU vide their letter dated 29th January, 2014 reg. The adverse impacts on the residents of Rajiv Gandhi South Campus due to the project. The same were presented before the Committee. The PP held meetings with BHU on 08.03.2014 and 10.03.2014 and detailed discussions were held on all the issues and provided satisfactory replies. The issues raised by the NGO, Vindhya Environmental Society in their letter to BHU were also discussed in the said meetings in detail. The Minutes of the said meeting were also submitted before the Committee. As desired by BHU, the commitments regarding installation and operation of ESP (with 99.9% efficiency) and ETP, complying with all conditions stipulated by CWC on water withdrawal and complying with proposed ash utilization plan shall be

	submitted to BHU. The committee recommended that the environmental cell of the PP shall also work in close coordination with BHU. To compound this issue further the appellants have pointed out that the persons who raised their concerns did not participate in the meeting nor they authorize any person to hold the meeting on their behalf; and Professor Dr. Vijay Kishna who is shown to have attended the meeting held on 8th and 10th March, 2014 in the minutes annexure R-26 (page 1183) asserted vide email dated 23rd April, 2014 that the said meetings were not authorized by Banaras Hindu University and he participated in his personal capacity (page 2061) annexure R-30; and this fact was brought to the notice of Secretary, MoEF by appellants no. 3 vide email dated 25th April, 2014 annexure R-31. It was therefore, incumbent upon the MoEF to have thoughtfully considered the relevant record and sought clarification from EAC before proceeding to grant the EC. Nothing of this sort is done in the present case.	
53	Learned Counsel appearing for the appellants submitted that transporting the massive quantity of Gangetic untreated/contaminated water to the rain fed upper Khajuri reservoir is bound to change the water quality of upper Khajuri reservoir and consequently have impact on the people downstream using the water for human needs. It is further submitted that water withdrawal of 36,000,000,000 litres annually would undoubtedly affect the ecological flow of Ganga and severely affect the Gangetic Biodiversity including Gangetic Dophins found in Mirzapur stretch; and it is wrongly presumed that water withdrawal during monsoon from Ganga would leave no impact on Gangetic environment when there is a record of decline in rainfall in past year with no sufficient water in river in monsoons vide statistical data of rainfall in District Mirzapur annexure A-28 (page 2058). According to Learned Counsel appearing for the appellants both competitive use of water from river Ganga and	विभिन्न कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुये भू–जल एवं सतह जल भण्डारण की गुणवत्ता में प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित फ्लाई ऐश एवं हानिकारक गैसो के कारण ह्रास होना स्वाभाविक है।

	upper khajuri reservoir and its comulative impact on upstream and downstream have not been discussed in the EIA report. We do find substance in the submission made.	
54	It is further pointed out that the Project Proponent revealed in Form-1 dated 03-12-2011 (entry serial no. 10, page no. 110) that the area in question does not fall in any important high quality or scarce resources zone (ground water resource, surface resource, forestry, agriculture, fishery, tourism and minerals), and the EIA report (page no. 633 and 634) disclosed that the project site does not fall in any economically viable zone as per Regional GSI map.	मीरजापुर जनपद में स्थित शुष्क पर्णपाती वन जो की विन्ध्य क्षेत्र के विशिष्ट वन क्षेत्रों में से एक है, के उत्तरी सीमा से गंगा नदी इन्ही विशिष्ट वन क्षेत्रों के जल ग्रहण क्षेत्रों से गुजरने वाली विभिन्न सहायक नदियों के जल को समेटती हुई प्रवाहित होती है। प्रस्तावित परियोजना के कारण जल ग्रहण क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से सतह जल भण्डारण एवं प्रवाह तथा सम्पूर्ण वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और नदियों की जल वहन क्षमता तथा जल की गुणवत्ता दोनो प्रभावित होगी। सम्पूर्ण आरक्षित वन क्षेत्र चैम्पियन एवं सेठ के वनो के वर्गीकरण के अनुसार 5बी/ई–1(एनागाईसेस पेडुला फारेस्ट), 5बी/ई–2 (बांसविलिया सेराटा फारेस्ट), 5बी/ई–5 (ब्यूटिया मोनोस्पर्मा फारेस्ट), 5बी/ई–9 (ड्राई बेम्बू फारेस्ट) शुष्क पर्णपाती वनो की श्रेणी में आता है जो विंध्यक्षेत्र की विशिष्ट वन सम्पदा है। उक्त सम्पूर्ण वन क्षेत्र पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील है। सम्पूर्ण क्षेत्रफल में क्वार्टजाइट, सैण्ड स्टोन आदि खनिज की बहुतायत है। सम्पूर्ण वन क्षेत्र पारिस्थितकीय रूप से संवेदनशील एवं विन्ध्य क्षेत्र का विशिष्ट वन क्षेत्र है। सम्पूर्ण वन क्षेत्र में प्रागैतिहासिक कालीन, लखनियां पेन्टिग, एवं सल्खन फाजिल पार्क उक्त 25.00 किमी0 की परिधि में पड़ने वाले कैमूर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत स्थित है। प्रस्तावित परियोजना के 10.00 किमी की परिधि के अन्तर्गत ही कई टूरिस्ट स्पाट है, यथा विण्ढमफाल,

		सिद्धनाथ दरी फाल आदि। इस प्रकार से प्रस्तावित परियोजना के कारण उक्त क्षेत्र की पूरी पारिस्थितिकी प्रभावित होगी।
55	The Appellants further points out that the respondent no. 4 in its reply (page no. 342) made reference to the Geological and Mineral Map of District Mirzapur annexure R-47 to state that the District Mirzapur has presence of Alluvium rather than Kaimur sand stone. Coloured map produced at annexure R-58 (page no. 2924) shows that the project area is adjacent to Marihan identified as a Kaimur sand stone area which is an important mineral resource.	सम्पूर्ण क्षेत्र में सैण्ड स्टोन एवं क्वार्डजाइट मिश्रित मृदा है। जो कि विन्ध्यक्षेत्र के विशिष्ट वन क्षेत्रों के विकास में सर्वथा सहायक है एवं शरीसृप वर्ग के वन्य जन्तु तथा माइक्रोफ्लोरा की अभिवृद्धि एवं संरक्षण में सहायक है।
60	EC Regulations, 2006 lay down a chain of interconnected processes to make a complete mechanism required to assess the potential impacts of the project or activities on the environment made of several components. Every piece of information/data furnished and/or collected at every stage of the process is expected to be wholesome free from any twist or turn in order to truly aid the correct appraisal of the potential impacts of the project. This expectation of law is evident from the checks and balances provided in EC Regulations, 2006.	प्रस्तावित परियोजना में निम्नलिखित दुष्प्रभाव परिलक्षित होना स्वाभाविक है। – क्षेत्र के तापमान में वृद्धि – वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में ह्रास – वन की साइट गुणवत्ता में ह्रास – जल संरक्षण में कमी – भू–जल रिचार्ज में कमी – सतह जल भण्डारण की गुणवत्ता व मात्रा में कमी। – सांस जनित बीमारियों में वृद्धि – पुरातात्विक व पर्यटन के क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव – सम्पूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र पर दुष्प्रभाव – वन्य जीव मानव संर्घष की घटनाओं में वृद्धि – नदियों के जल वहन क्षमता व जल की गुणवत्ता में ह्रास ये सभी अर्न्तवलित समस्याएं अत्पन्न होगी जो विभिन्न तापीय विद्युत परियोजनाओं के पूर्व के दुष्प्रभावों के अनुभवों पर आधारित है साथ ही प्रत्यक्ष रूप से आगणित समस्याओं को उत्प्रेरित करेगी।

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर